दबाव का असर ◆ उद्योग के कड़े रुख के बाद राहत देने पर विचार

चीनी उद्योग को केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलने के आसार

शरद पवार समेत वरिष्ठ मंत्रियों ने राहत के लिए उपायों पर चर्चा की

बिजनेस भास्कर ◆ नई दिल्ली

आर्थिक संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को केंद्र सरकार राहत दे सकती है। इस मसले पर केबिनेट कमेटी की बैठक में चीनी निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉ बैक को 1.3 फीसदी से बढ़ाने के साथ ही रॉ-शुगर आयात के बदले व्हाइट चीनी की निर्यात अवधि में कमी किए जाने की संभावना है। साथ ही चीनी मिलों को बैंकों से लिए जाने वाले ऋण के ब्याज का भुगतान शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से किए जाने की भी योजना है।

चीनी उद्योग के कड़े रुख के बाद बुधवार को हरकत में आई केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में वित्त मंत्री पी चिदंबरम और नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह के बीच चीनी उद्योग को राहत देने के विभिन्न उपायों पर बात हुई।

बैठक के बाद कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि चीनी उद्योग को राहत देने के लिए तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ है इस मसले पर केबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह ने पत्रकारों से कहा कि चीनी उद्योग घाटे का सामना कर रहा है जबकि मिलों द्वारा पेराई शुरू नहीं करने से किसानों को भी घाटा हो रहा है। बैठक में चीनी उद्योग को राहत देने के लिए विभिन्न उपायों जैसे रॉ-शुगर के आयात को रिफाइंड करके निर्यात करने की अवधि को घटाने पर विचार-विमर्श हुआ। इस समय चीनी मिलें रॉ-शुगर को आयात करके 18 महीने में निर्यात कर सकती हैं। इस अवधि को केंद्र सरकार घटाकर 3 महीने कर सकती है। चीनी निर्यात पर इस समय ड्यूटी ड्रा बैक 1.3 फीसदी है, इसमें भी बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें उत्पाद शुल्क की ऐवज में बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती हैं तथा इसके ब्याज का भुगतान एसडीएफ फंड से किया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीनी मिलों को प्रति क्विंटल 71 रुपये उत्पाद शुल्क देना होता है, इस आधार पर पेराई सीजन 2012-13 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान चीनी मिलों ने उत्पाद शुल्क के रूप में लगभग 1,750 रुपये करोड़ का राजस्व दिया है जबकि इस समय शुगर डेवलपमेंट फंड में करीब 900 करोड़ रुपये जमा है।

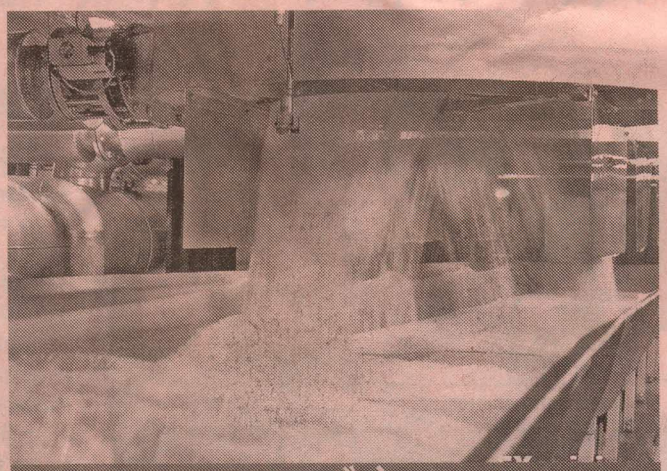

राहत कैसे

- चीनी निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉ बैक बढ़ाने पर चर्चा
- आयातित रॉ-शुगर की रिफाइनिंग की अवधि घटेगी
- अवधि 18 माह से घटकर 3 माह करने का विचार
- मिलों को डेवलपमेंट फंड से ब्याज में राहत संभव

चीनी वायदा में मजबूती

मुंबई ◆ वायदा कारोबार बुधवार को चीनी के दाम सुधर गए। इससे पहले इसके दाम करीब डेढ़ साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। चीनी मिलों को राहत दिए जाने की उम्मीद में यह तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा गन्ना उत्पादक राज्यों में पेराई लेट होने से भी तेजी को बल मिला। एनसीडीईएक्स में चीनी नवंबर वायदा 0.55 फीसदी बढ़कर 2950 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।

मुंबई के एक डीलर ने कहा कि किसानों और मिलों के बीच गन्ने के मूल्य को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। सरकार मिलों को सस्ते कर्ज के रूप में सब्सिडी देकर वित्तीय मदद भी कर सकती है। (प्रेट्र)

Business Bhaskar
21/11/13